compulsory that the trains would move only on having ten coaches out of which at least one will be sleeper and one first Class coach; and

(c) what are the names of originating, stations where no facility has been provided for replacing the defective coaches with the other ones?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K. C. LENKA): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

शाहगंज और मऊ के बीच बड़ी रेलवे लाइन का बनाया जाना

397. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार शाहगंज तथा मऊ के बीच बड़ी रेलवे लाइन बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका): (क) और (ख) मऊ और शाहगंज के बीच मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव योजना आयोग को भेज दिया गया है। उनका अनुमोदन प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल लाइन को दोहरा बनाने के कार्य को कम प्राथमिकता दिया जाना

398. **श्री राम सिंह राठवा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेल लाइन को दोहरा बनाने के कार्य को कम प्राथमिकता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो दोहरी लाइन का जोनवार प्रतिशत कितना है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में नई लाइनों को बिछाने, छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और रेलवे लाइन को दोहरा बनाने से संबंधित प्रति वर्ष कुल कितना काम किया गया है और उक्त समग्र कार्य में से रेल लाइन को दोहरा करने के कार्य की प्रतिशतता क्या थी; और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई संदर्शी योजना तैयार की है और इस कार्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका): (क) जी, नहीं।

(ख) दोहरी लाइन की जोन-वार प्रतिशतता निम्नलिखित अनुसार है:—

(1)	मध्य रेलवे	— 45.5%
(2)	पूर्व रेलवे	— 42.4%
(3)	उत्तर रेलवे	— 20.5%
(4)	पूर्वोत्तर रेलवे	— 0.5%
(5)	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	— 3.4%
(6)	दक्षिण रेलवे	— 13.7%
(7)	दक्षिण-मध्य रेलवे	— 21.4%
(8)	दक्षिण-पूर्व रेलवे	— 37.1%
(9)	पश्चिम रेलवे	— 17.1%

(ग) पिछले तीन वर्षों में नई लाइन परिवर्तन और दोहरी लाइन बिछाने के लिए कुल परिव्यय निम्नलिखित अनुसार है:—

वर्ष	कुल परिव्यय	दोहरी लाइन पर परिव्यय	प्रतिशतता
1991-92	रु० 672 करोड़	रु० 284 करोड़	42.26%
1992-93	रु० 1180 करोड़	रु० 214 करोड़	18.14%
1993-94	रु० 1223 करोड़	रु० 220 करोड़	17.99%

(घ) जी, हां। प्रत्येक वर्ष लगभग 200-250 कि०मी० दोहरी लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है।

Running of Shatabadi Express between New Delhi and Amritsar

399. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of RAILWAYS be plased to state:

(a) whether Government are considering to start Shatabdi Express train between New Delhi and Amritsar;

(b) if so, by when; and

(c) if not, what are the reasons

therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K.C. LENKA): (a) There is no proposal at present.

(b) Does not arise.

(c) Operational constraints and lack of resources.

Complaints against Railway Staff/ Administration

400. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that complaints against railway staff/administration are on the increase;

(b) if so, what are the reasons therefor;

(c) the number of complaints decided against railway establishments/railway administration during the last three years; and

(d) what action the railways administration is contemplating against the erring employees causing commuters hardship, resulting in complaints to consumers forum?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K.C. LENKA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Consumer Disputes Redressal Forums decided 122 cases during 1991-92, 122 during 1992-93 and 140 cases during 1993-94 (upto 31.12.93) against the railways.

(d) Besides taking disciplinary action against them, counselling of such staff is also done.

उत्तर प्रदेश में उपरि पुलों का निर्माण

401. **श्री आनन्द प्रकाश गौतम:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे सुरक्षा निधि से उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे उपरिपुलों का निर्माण किया जा चुका है और इस निधि की मदद से कितने उपरिपुलों का निर्माण अभी चल रहा है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने इन उपरिपुलों पर खर्च की गयी कुल धनराशि के रेलवे के भाग के रूप में 28.52 करोड़ रुपये की धनराशि के लिए प्रतिपूर्ति का दावा भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है;

(ग) इस मद में अंशदान के रूप में भारत सरकार (रेल मंत्रालय) द्वारा कितनी धनराशि दी गयी है और कितनी धनराशि अभी दी जानी शेष है; और

(घ) अंशदान की बकाया धनराशि का कब तक भुगतान कर दिया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका): (क) से (घ): रेलें उन व्यस्त समपारों को लागत में हिस्सेदारी के आधार पर सड़क ऊपरी/निचले पुलों से बदलने पर विचार करती है, जहां यातायात गाड़ी वाहन इकाई (यह एक ऐसा आंकड़ा है जो 24 घंटे में गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या को वहां से गुजरने वाली सड़क यातायात की संख्या से गुणा करके प्राप्त किया जाता है) के अनुसार एक लाख से अधिक होता है। ऊपरी सड़क पुलों तथा निचले सड़क पुलों के निर्माण पर राज्य सरकारों द्वारा किया गया खर्च उनके क्रेडिट में धन की उपलब्धता की सीमा तक रेलवे संरक्षा निर्माण कार्य निधि से उन्हें प्रतिपूरित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त 28.52 करोड़ रु० मूल्य के दावों में से, 12.68 करोड़ रु० मूल्य के दावों का सत्यापन कर दिया गया है। इसमें से, 7.98 करोड़ रु० उत्तर प्रदेश सरकार को पहले ही प्रतिपूरित कर दिए गये हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा बजट अनुदान के माध्यम से अतिरिक्त धन रिलीज करने पर आगे की प्रतिपूर्ति निर्भर करेगी।